

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड
माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड की
82वीं बैठक दिनांक 25 अगस्त, 2022,

कार्यसूची (एजेण्डा)

एजेण्डा संख्या – 1	सरकार द्वारा प्रायोजित रोजगार सृजन ऋण योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट i) केन्द्र सरकार प्रायोजित ऋण योजनायें : (क) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (ख) एन.यू.एल.एम. (ग) पी.एम.ई.जी.पी. (घ) एन.आर.एल.एम. (ङ) स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (च) पी.एम. स्वनिधि ii) राज्य सरकार प्रायोजित ऋण योजनायें : (क) मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (ख) मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना – नैनो (ग) मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना (घ) वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना (ङ) पं. दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम-स्टे) योजना
एजेण्डा संख्या – 2	वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय रणनीति (NSFI) 2019-2024 : (क) सामाजिक सुरक्षा योजना (ख) बिजनेस कॉरिस्पोंडेंट एवं कैपेसिटी बिल्डिंग (ग) कॉमन सर्विस सेन्टर को बिजनेस कॉरिस्पोंडेंट के कार्य प्रदान करना (घ) वित्तीय साक्षरता केन्द्र (FLC) (ङ) बैंकिंग सुविधा से अनाच्छादित गाँव (च) चार धाम यात्रा मार्ग पर बैंक शाखायें खोलना
एजेण्डा संख्या – 3	कृषि विषयक योजनायें : (क) कृषि अवसंरचना निधि (AIF) (ख) प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME)
एजेण्डा संख्या – 4	योजनावार एन.पी.ए. की समीक्षा
एजेण्डा संख्या – 5	(क) एम.एस.एम.ई. (ख) ईमरजेन्सी क्रेडिट लाईन गारंटी योजना
एजेण्डा संख्या – 6	लम्बित प्रकरण (i) Issues pending with State Government (ii) Issues of SLBC pending with Banks
एजेण्डा संख्या – 7	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड
82वीं बैठक दिनांक 25 अगस्त, 2022 की कार्य सूची (एजेण्डा)

एजेण्डा

81वीं बैठक :

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड की 81वीं बैठक दिनांक 03 अगस्त, 2022 को सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आयोजित की गयी थी।

एजेण्डा संख्या – 1 :

सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं की प्रगति :

केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं की प्रगति (F.Y. 2021-22) :

Scheme		F.Y. 2019-20			F.Y. 2020-21			F.Y. 2021-22		
		Target	Sanctioned	Progress %	Target	Sanctioned	Progress %	Target	Sanctioned	Progress %
NRLM		7610	8089	106	9740	7644	99	10,000	10,312	103
MUDRA		---	198945	---	---	191061	---	1,90,000	2,03,767	107
SCP	SC	1463	1082	74	732	774	106	805	823	102
	ST	100	96	96	100	70	70	100	105	105
	Minority	225	92	41	177	78	44	150	77	51
	Total	1788	1270	71	1009	922	91	1,055	1,005	95
NULM		1000	797	80	772	1084	140	2,330	1,267	54
PM SVANidhi		---	---	---	25000	9848	39	25000	11400	46
Stand-up India		2198	506	23	2260	409	18	2198	264	12
PMEGP		1318	1840	140	1326	2627	198	1,714	1,917	112
					Margin Money Target : Rs. 39.77 Cr. Achievement : Rs. 45.19 Cr. (114 %)			Margin Money Target : Rs. 51.71 Cr. Achievement : Rs.34.37 Cr. (66%)		

राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं की प्रगति (F.Y. 2021-22) :

Scheme		F.Y. 2019-20			F.Y. 2020-21			F.Y. 2021-22		
		Target	Sanctioned	Progress %	Target	Sanctioned	Progress %	Target	Sanctioned	Progress %
VCSGSY	Vehicle	147	140	95	147	137	93	150	117	78
	Non Vehicle	153	53	35	153	60	39	100	56	56
Home Stay		---	115	---	---	128	---	200	125	62
MSY		NA	NA	NA	1500	3866	258	5100	5583	109
MSY - NANO		NA	NA	NA	NA	NA	NA	---	1024	---
MSSY		NA	NA	NA	NA	NA	NA	---	122	---

(i) केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनायें :

(क) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना :

(Annex. – 1)
(रु. करोड़ में)

		F.Y. 2021-22		Upto 31.07.2022	
		खातों की संख्या	स्वीकृत ऋण राशि	खातों की संख्या	स्वीकृत ऋण राशि
षिषु	रु. 50000 तक के ऋण	132426	400.21	46629	148.81
किषोर	रु. 50000 से रु. 5.00 लाख	60238	1086.91	17612	368.25
तरुण	रु. 5.00 लाख से रु. 10.00 लाख	11103	909.51	4294	357.82
योग		203767	2396.63	68535	874.91

Source : Mudra Portal

बैंकों द्वारा मुद्रा योजना अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों जैसे : व्यापारिक, सेवा, निर्माण, कृषि हेतु रु. 10.00 लाख तक के ऋण स्वीकृत किये जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजना अंतर्गत **68535** लाभार्थियों को **रु. 874.91 करोड़** के ऋण स्वीकृत किए गए हैं तथा अनुमानतः **94735** व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में योजना अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य रु. 2500.00 करोड़ के सापेक्ष **203767** लाभार्थियों को **रु. 2396.63 करोड़** के ऋण स्वीकृत किए गए हैं तथा अनुमानतः **2,86,211** व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

(ख) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन व्यक्तिगत (NULM Individual) :

(Annex. – 2)
(रु. लाखों में)

प्रगति	वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
Upto 31/07/22	1000	714	345	341	472.45	105	264
F.Y. 2021-22	2330	3126	1267	1252	1775.94	482	1438

Source : NULM Portal

वित्तीय वर्ष 2022-23 में बैंकों द्वारा योजना अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य **1000** के सापेक्ष **345** ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं, जो कि लक्ष्य का **35%** है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में बैंकों द्वारा योजना अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य **2330** के सापेक्ष **1267** ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं, जो कि लक्ष्य का **54%** है।

(ग) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम (PMEGP) :

प्रधान कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के परिपत्र संख्या PMEGP/Policy/2022-23 दिनांक 01.06.2022 के अनुसार संशोधित दिषा-निर्देशानुसार निम्नवत हैं :

- पीएमईजीपी योजना वर्ष 2025-26 तक संचालित रहेगी।
- विनिर्माण क्षेत्र में परियोजना की कुल लागत रु. 25.00 लाख को बढ़ाकर रु. 50.00 लाख कर दिया गया है।
- सेवा क्षेत्र में परियोजना की कुल लागत रु. 10.00 लाख को बढ़ाकर रु. 20.00 लाख कर दिया गया है।

योजना अंतर्गत प्रगति निम्नवत है :

(Annex. – 3)
(रु. लाखों में)

प्रगति	वार्षिक लक्ष्य	प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	ऋण राशि	वितरित आवेदन पत्र	ऋण राशि	निरस्त आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र	
								<1M	>1M
Upto 31.07.22	1714	1783	593	2228.92	122	694.56	583	205	402
F.Y. 2021-22	1714	4780	1917	11475.96	1603	8223.53	2505	202	156

(Source : PMEGP Portal)

वित्तीय वर्ष 2022-23 में 31.07.2022 तक योजना अंतर्गत मार्जिन मनी हेतु निर्धारित लक्ष्य रु. **51.71 करोड** के सापेक्ष रु. **8.24 करोड (16%)** की प्रगति दर्ज की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर योजना अंतर्गत मार्जिन मनी वितरण हेतु निर्धारित लक्ष्य रु. **51.71 करोड** के सापेक्ष बैंकों द्वारा रु. **34.37 करोड (66%)** की प्रगति दर्ज की गयी है।

बैंकों से आग्रह है कि वे योजना अंतर्गत निर्धारित वार्षिक लक्ष्य का 75 प्रतिशत लक्ष्य त्रैमास दिसम्बर, 2022 तक पूर्ण करें।

पोर्टल में नोडल बैंक द्वारा निरस्त की गयी मार्जिन मनी के आवेदन पत्र पुनः सुधार कर पोर्टल में अपलोड करें।

(घ) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) :

(Annex. – 4)
(रु. लाखों में)

प्रगति	वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	ऋण राशि	निरस्त आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र	
						< 1 M	>1 M
Upto 31.07.2022	15000	5430	730	975.05	404	2421	1875
F.Y. 2021-22	10000	16213	10312	168.96	5342	36	523

Source : NRLM Portal

वित्तीय वर्ष 2022-23 में बैंकों द्वारा योजना अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य **15000** के सापेक्ष **730** ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में बैंकों द्वारा योजना अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य **10000** के सापेक्ष **10312** ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं, जो कि लक्ष्य का **103%** है।

एन.आर.एल.एम. पोर्टल वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम त्रैमास में कार्य नहीं कर रहा था। समस्त बैंकों को अवगत कराया गया है कि वे योजना अंतर्गत स्वीकृत ऋण आवेदन पत्रों को पोर्टल में दर्ज करें।

(ङ) स्पेशल कम्पोनेंट प्लान (SCP) :

(Annex. – 5)
(रु. लाखों में)

Progress as on 31.07.2022

योजना	वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित/प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त/वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
अनुसूचित जाति	886	411	154	139	90.86	27	230
अनुसूचित जनजाति	100	25	10	8	3.85	0	15
अल्पसंख्यक समुदाय	120	35	14	14	9.57	0	21
कुल योग	1106	471	178	161	104.28	27	266

Source : Deptt.

Progress F.Y. 2021-22

(रु. लाखों में)

योजना	वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित/प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त/वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
अनुसूचित जाति	805	1528	823	779	568.91	377	328
अनुसूचित जनजाति	100	131	105	100	46.15	17	9
अल्पसंख्यक समुदाय	150	178	77	77	84.04	24	77
कुल योग	1055	1837	1005	956	699.10	418	414

Source : Deptt.

वित्तीय वर्ष 2022-23 में बैंकों द्वारा योजना अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य 1106 के सापेक्ष 178 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं, जो कि लक्ष्य का 16% है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में बैंकों द्वारा योजना अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य 1055 के सापेक्ष 1005 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं, जो कि लक्ष्य का 95% है।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को कृषि, सेवा, व्यवसाय, यातायात हेतु रु. 20,000.00 से रु. 7.00 लाख तक की परियोजना लागत तक ऋण स्वीकृत किया जाता है। योजना अंतर्गत 50 प्रतिषत या अधिकतम रु. 10,000.00 का षासकीय अनुदान एवं योजना की लागत का 25 प्रतिषत मार्जिन मनी ऋण 4 प्रतिषत वार्षिक ब्याज दर पर निगम द्वारा लाभार्थी को बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।

(च) पी.एम. स्वनिधि (PM SVANidhi) :

पी.एम. स्वनिधि आई.टी. टीम द्वारा अवगत कराया गया है कि पी.एम. स्वनिधि के आवेदकों द्वारा ग्राहक सेवा केन्द्र/आधार केन्द्र में पहुंचकर अपने आधार कार्ड में आवेदन पत्र में दिया गया अपना मोबाईल संख्या अपडेट कराना होगा। Re-KYC होने के उपरांत 2nd Tranche का आवेदन पत्र वित्तीय संस्थानों के पास नये आवेदन पत्र श्रेणी में पदरिषत होंगे।

PM SVANidhi - 1st Tranche (upto Rs. 10,000/-) :

(Annex. – 6)

progress	Total Applications	Rejected	Ineligible	Eligible	Total Sanctioned	Pending	Disbursement	Pending for Disbursement
	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.
Upto 31/07/22	24688	4719	1054	18905	13146	5769	11729	1417
Upto 31/03/22	18594	4374	976	--	11400	---	10862	---

(Source : PM SVANidhi Portal)

PM SVANidhi - 2nd Tranche (Rs. 10,000/- to Rs. 20,000/-)**Progress as on 20/08/2022**

Eligible Applications	Sanctioned	Disbursed	Returned by Bank	Ineligible	Pending for Consent (e-KYC)
No.	No.	No.	No.	No.	No.
3115	1993	1265	0	0	3153

Progress F.Y. 2021-22

Total Applications	Total Picked up	Total Sanctioned	Total Disbursed	Rejected	Ineligible
No.	No.	No.	No.	No.	No.
906	297	507	412	102	00

- मंत्रालय से प्राप्त दिषानिर्देशानुसार 2nd Tranche हेतु “Rejection” का आप्पन हटा दिया गया है, अतः अब ऋण आवेदन पत्र किसी भी स्थिति में निरस्त नहीं किये जा सकते हैं।

- इस संदर्भ में सिडबी द्वारा अवगत कराया गया है कि यह एक **policy decision** है, अतः बैंक के नियंत्रकों से आग्रह है कि वे अपनी शाखाओं को पोर्टल में 2nd Tranche एवं 3rd Tranche की समस्त ऋण आवेदन पत्रों को स्वीकृत एवं वितरित करने हेतु उचित निर्देश जारी करें।
- बैंकों से आग्रह है कि वे पी.एम. स्वनिधि ऋण कि लिए न्यूनतम सिबिल स्कोर की बाध्यता को समाप्त करने के लिए अपने बैंक बोर्ड से अनुमति प्राप्त करें।

PM SVANidhi - 3rd Tranche (Rs. 20,000/- to Rs. 50,000/-) :

Progress as on 20/08/2022

Eligible Applications	Sanctioned	Disbursed	Returned by Bank	Ineligible	Pending for Consent (E-KYC)
No.	No.	No.	No.	No.	No.
13	10	07	0	0	01

योजना अंतर्गत माह जुलाई, 2022 तक 1st Tranche में 13146, 2nd Tranche में 1993 तथा 3rd Tranche में 10 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये हैं।

यू.एल.बी. से आग्रह है कि वे वैंडर का अतिषिघ्न e-KYC करवायें, जिससे बैंक शाखायें ऋण स्वीकृत कर सकें।

(ii) राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनायें :

(क) मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY) :

(Annex. – 7)

Progress	Target	Pending Applications of Last F.Y.	Applications Sent to Bank	Reverted	Returned	Sanctioned	Disbursed	Pending
	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.
Upto 31.07.2022	6000	*	5271	506	1070	1267	858	2428
F.Y. 2021-22	5100	1017	13072	1939	4268	5583	4277	2299

(Source of Data – MSY Portal)

वित्तीय वर्ष 2022–23 में बैंकों द्वारा योजना अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य 6000 के सापेक्ष 1267 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं, जो कि लक्ष्य का 21% है।

* उद्योग विभाग को इस विषयक सूचना प्रेषित कर दी गयी है।

एम.एस.वाई. पोर्टल में वित्तीय वर्ष 2021–22 के लम्बित ऋण आवेदन पत्र वित्तीय वर्ष 2022–23 में लम्बित दर्शाये जा रहे हैं, जिनका मिलान नहीं हो पा रहा है।

बैंकों से आग्रह है कि वे योजना अंतर्गत निर्धारित वार्षिक लक्ष्य का 75 प्रतिशत लक्ष्य त्रैमास दिसम्बर, 2022 तक पूर्ण करें।

समस्त बैंक योजना अंतर्गत प्रथम किस्त निर्गत करने के उपरांत पोर्टल में मार्जिन मनी सब्सिडी लॉज करें तथा आवेदक को पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन ईडीपी प्रशिक्षण एवं विभिन्न संस्थानों से ऑफलाईन ईडीपी प्रशिक्षण लेने हेतु अवगत करायें।

(ख) मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना – नैनो (MSY - NANO) :

(Annex. – 8)

Progress	Target	Applications Sent to Bank	Returned	Rejected	Sanctioned	Disbursed	Pending
	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.
Upto 31.07.2022	10000	4017	594	1284	1289	797	850
F.Y. 2021-22	---	3867	444	899	1024	586	1500

(Source of Data – MSY Portal)

वित्तीय वर्ष 2022-23 में बैंकों द्वारा योजना अंतर्गत **1289** ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में बैंकों द्वारा योजना अंतर्गत **1024** ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं।

एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड द्वारा समस्त बैंकों को अवगत कराया गया है कि वे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म (नैनो) उद्यम को मुद्रा ऋण योजना (षिषु) से सम्बद्ध करते हुए आच्छादित करने हेतु कार्य करें। समस्त बैंक शाखायें उक्त योजना का लाभ मुद्रा ऋण योजना (षिषु) के अंतर्गत आवेदकों को ऋण प्रदान कर।

(ग) मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना (MSSY):

(Annex. – 9)

Progress	Backlog	Applications Sent to Bank	Returned	Rejected	Sanctioned	Disbursed	Pending
	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.
Upto 31.07.2022	9	144	29	28	51	43	45
F.Y. 2021-22	69	420	107	157	122	90	103

(Source of Data – MSY Portal)

वित्तीय वर्ष 2022-23 में बैंकों द्वारा योजना अंतर्गत **51** ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में बैंकों द्वारा योजना अंतर्गत **122** ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं।

बैंकों से आग्रह है कि वे अपने कार्पोरेट कार्यालय से राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजना विषयक Circular एवं Product Code जारी करायें।

(घ) वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना :

(Annex. – 10)

Progress Upto 31.07.2022

(रु. करोड़ में)

वार्षिक लक्ष्य		प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
खण्ड	संख्या						
वाहन	150	126	57	47	5.17	17	52
गैर-वाहन	100	73	18	15	4.97	16	39
कुल योग	250	199	75	62	10.14	33	91

Progress F.Y. 2021-22

(रु. करोड़ में)

वार्षिक लक्ष्य		प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
खण्ड	संख्या						
वाहन	150	178	117	106	10.48	39	22
गैर-वाहन	100	133	56	50	13.96	41	36
कुल योग	250	311	173	156	24.44	80	58

वित्तीय वर्ष 2022-23 में बैंकों द्वारा योजना अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य 250 के सापेक्ष **75** ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं, जो कि लक्ष्य का 30% है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में बैंकों द्वारा योजना अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य 250 के सापेक्ष **173** ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं, जो कि लक्ष्य का 69% है।

(ङ) पं. दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) योजना :

(Annex. – 11)

(रु. करोड़ में)

प्रगति	वार्षिक लक्ष्य	प्राप्त ऋण आवेदन पत्र	स्वीकृत ऋण आवेदन पत्र	वितरित ऋण आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त / वापिस ऋण आवेदन पत्र	लम्बित ऋण आवेदन पत्र
Upto 31.07.2022	200	243	49	49	856.15	44	150
F.Y. 2021-22	200	338	125	124	2565.00	94	119

(Source – Tourism Deptt.)

उक्त योजना अंतर्गत बैंक ऐसे ऋण आवेदन पत्रों का अविलम्ब निस्तारण करें, जिनमें सेक्शन 143 अंतर्गत अकृषि प्रमाण पत्र एवं निर्माणाधीन इकाई का मानचित्र अधिकृत एजेन्सी से स्वीकृत नहीं हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में बैंकों द्वारा योजना अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य 200 के सापेक्ष 49 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं, जो कि लक्ष्य का 24% है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में बैंकों द्वारा योजना अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य 200 के सापेक्ष 125 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं, जो कि लक्ष्य का 62% है।

एजेण्डा संख्या – 2 :

वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय रणनीति (NSFI) 2019-2024 :

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय नीति (NSFI) 2019-2024 घोषित की गयी है।

(क) सामाजिक सुरक्षा योजना :

वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जन सुरक्षा योजनाओं हेतु दिनांक 02.10.2021 से 30.09.2022 तक संतृप्तता अभियान प्रारम्भ करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों को निर्देशित किया गया है।

योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए बैंकों द्वारा निम्नवत प्रगति दर्ज की गयी है :

(Annex. – 12)

योजना	आच्छादित खातों की संख्या			
	As on 31.03.2020	As on 31.03.2021	As on 31.03.2022	As on 30.06.2022
पी.एम.जे.डी.वाई (PMJDY)	26,97,781	28,59,104	30,39,442	30,97,660
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)	16,77,754	20,43,505	22,62,442	22,50,617
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJY)	4,35,773	4,59,346	5,58,148	5,67,774
अटल पेंशन योजना (APY)	2,06,556	2,81,786	3,93,453	4,64,840

(Source : F.I. Plan Portal - PMJDY, Banks - PMSBY, PMJJBY, PFRDA - APY)

Update on Social Security Scheme :

Sr. No.	Scheme Name	As on	Information	Country	Uttarakhand
1	PMJDY	22/06/2022	Deposit in PMJDY Accounts (Rs. In Cr.)	1,68,835.06	1,651.67
			No. of Female PMJDY Accounts	25,49,71,011	15,67,602
2	PMJJBY	15/06/2022	Cumulative PMJJBY Enrollments	12,96,85,949	7,01,822
			Claims amount Paid (Rs. In Cr.)	11,774.84	74.40
3	PMSBY	15/06/2022	Cumulative PMSBY Enrollments	28,80,64,259	28,17,396
			Claims amount Paid (Rs. In Cr.)	1,976.35	38.86
4	APY	31/05/2022	Total number of APY Subscribers	4,14,06,657	4,49,204

(Source : DFS)

Comparitive performance of Uttarakhand State Flagship Schemes (per lakh population) with National Average :

Sr.	Parameter	Uttarakhand	Country
1	PMJDY Accounts per lakh population	29,374	37,853
2	PMJJBY enrollments per lakh population	6,958	10,710
3	PMSBY enrollments per lakh population	27,933	23,790
4	APY Subscribers per lakh population	4,454	3,420

(Source : DFS)

(ख) बिजनेस कॉर्रेस्पोंडेंट एवं कैपेसिटी बिल्डिंग :

(Annex. – 13)

Progress	Total No. of B.C..	Active B.C.	In-Active B.C.	No. of B.C. completed B.C. Certification Course	No. of remaining B.C. for completion of B.C. Certification Course
As on 30.06.22	3816	3472	344	2434	1382
As on 31.03.22	3686	3317	369	2258	1428

- एक्सिस बैंक द्वारा 31.12.2021 को बी.सी. की संख्या 101 रिपोर्ट की गयी थी, जो कि जून, 2022 त्रैमास में बढ़कर 823 हो गयी है।
- मार्च, 2022 में 2258 बी.सी. द्वारा बी.सी. सर्टिफिकेशन कोर्स पूर्ण किया गया था तथा जून, 2022 तक 2434 बी.सी. द्वारा बी.सी. सर्टिफिकेशन कोर्स पूर्ण कर लिया गया है।

(ग) कॉमन सर्विस सेन्टर को बिजनेस कॉर्रेस्पोंडेंट के कार्य प्रदान करना :

- एक्सिस बैंक के 823 बी.सी. राज्य में सी.एस.सी. का कार्य कर रहे हैं।
- बैंकों से आग्रह है सी.एस.सी. को बी.सी. के कार्य करने हेतु अधिकृत करें तथा उन बी.सी. की सूची एस.एल. बी.सी. को प्रेषित करें, जो सी.एस.सी. का कार्य कर रहे हैं।

(घ) वित्तीय साक्षरता केन्द्र (FLC) :

राज्य में 16 वित्तीय साक्षरता केन्द्र कार्यरत हैं, जिनकी दिनांक 30.06.2022 की प्रगति रिपोर्ट निम्नवत है :

Sr. No.	District	FLC Trainer	Name of Sponsoring	FLC Manager				Rural Branches	
				No. of Sepcial Camps	participant	No. of specific Camps	Participants	Camps	
1	Uttarkashi	LDM	SBI	6	74	15	187		218
2	New Tehri	LDM	SBI	6	124	13	279		36
3	Chamoli	LDM	SBI	6	138	15	492		74
4	Champawat	LDM	SBI	6	213	16	431		90
5	Bageshwar	LDM	SBI	13	323	15	380		95
6	Pithoragarh	LDM	SBI	8	224	9	272		160
7	Rudraprayag	LDM	SBI	2	61	8	218		16
8	Pauri	LDM	SBI	5	96	8	133		384
9	Almora	LDM	SBI	5	158	8	256		137
10	Dehradun	Hired Trainer	PNB	5	138	29	967		139
11	Haridwar	Hired Trainer	PNB	6	241	16	375		207
12	Nainital	Hired Trainer	BOB	10	309	27	669		162
13	US Nagar	Hired Trainer	BOB	5	143	12	340		319
14	Tehri	Hired Trainer	UGB	4	50	6	138	Rural Camps	2037
15	Nainital	Hired Trainer	UGB	7	370	16	425	Special Camps	100
16	US Nagar	Hired Trainer	UGB	6	158	15	396	Specific Camps	228
			TOTAL	100	2820	228	5958	---	---
								Total Camps	2365

- वित्तीय साक्षरता केन्द्रों द्वारा जून, 2022 में 2365 कैम्पों का आयोजन वित्तीय साक्षरता हेतु किया गया है, जिसमें 8778 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया है।

(ङ) बैंकिंग सुविधा से अनाच्छादित गाँव :

अंतर-राज्य परिषद सचिवालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धषासकीय पत्र संख्या 05/01/2021-ZCS (C) दिनांक 06.05.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड राज्य में 244 गांव में बैंक/इण्डियन पोस्ट पेमेंट बैंक की शाखा कार्यरत नहीं है तथा इनमें से 33 गांव 10 किमी० की परिधि से अधिक दूरी के अंतर्गत आते हैं।

अग्रणी जिला प्रबन्धकों से प्राप्त जानकारी निम्नवत है :

- उत्तराखण्ड राज्य में बैंकिंग सुविधा से वंचित 244 गांवों में से 30 गांवों में बैंकिंग सुविधा (5 किमी. की परिधि में) उपलब्ध है।
- India Post Payment Bank द्वारा अवगत कराया गया है कि उन्हें 11 गांवों में शाखाएँ खोलने की स्वीकृत प्राप्त हैं तथा इन स्थानों पर 3G/4G internet connectivity उपलब्ध होने पर शीघ्र ही शाखाएँ संचालित कर दी जायेगी।
- उपरोक्त समस्त 244 गांवों में Banking Correspondents द्वारा बैंकिंग सेवाएँ प्रदान की जा रही है।
- ITDA द्वारा अवगत कराया गया है कि 131 गांवों में 3G/4G connectivity उपलब्ध है, किन्तु इन गांवों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव तथा जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण वित्तीय लेन देन काफी कम होने के दुषि्टगत बैंकिंग शाखाएँ खोलना व्यवहारिक नहीं है।
- 89 गांवों में कोई internet सुविधा उपलब्ध नहीं है। 24 गांवों में मात्र 2G connectivity है, जो बैंक संचालन के लिये पर्याप्त नहीं है।
- 71 गांवों में सड़क सुविधा उपलब्ध नहीं है।
- 34 गांवों में सोलर पावर की सुविधा उपलब्ध है, जो बैंकिंग संचालन के लिये पर्याप्त नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उत्तराखण्ड के दूरस्थ क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधा, जनसंख्या घनत्व न्यून होने तथा सड़क मार्ग उपलब्ध न होने के कारण राज्य में [बैंक/इण्डिया](#) पोस्ट पेमेंट बैंक की शाखाएँ खोला जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

इस क्रम में उत्तराखण्ड राज्य की ओर से अनुरोध है कि उत्तराखण्ड क समस्त दूरस्थ क्षेत्रों में इन्टरनेट कनेक्टिविटी प्रदान किये जाने हेतु उत्तराखण्ड राज्य को विषय पैकेज प्रदान किये जाने पर विचार किया जाय, ताकि उत्तराखण्ड राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में भी दूरसंचार सुविधा उपलब्ध करायी जा सके, [बैंक/इण्डिया](#) पोस्ट पेमेंट बैंक की शाखाएँ खोली जा सके तथा लोगों को दूरसंचार एवं बैंकिंग जैसी मूलभूत सुविधा प्रदान की जा सके तथा लोगों का जीवन स्तर सुधारा जा सके।

(च) चार धाम यात्रा मार्ग पर बैंक शाखाएँ खोलना :

चार धाम यात्रा मार्ग पर नई प्रस्तावित बैंक शाखाएँ :

Sr.	Bank Name	Proposed Branch to be opened on Char Dham Routes			
		Gangotri	Yamnotri	Badrinath	Kedarnath
1	State Bank of India	Survey given to LDM Uttarkashi for opening branch at Gangotri	Survey given to LDM Uttarkashi for opening branch at Yamnotri	Already one Branch of SBI at Badrinath with ATM	Kedarnath (Premises to be provided by State Govt. for proposed Br. opening)
2	Punjab National Bank	---	---	---	---
3	Bank of Baroda	---	---	---	---
4	Union Bank of India	---	---	---	---
5	Canara Bank	---	---	---	---
6	Axis Bank	---	---	---	---
7	ICICI Bank	---	---	---	---
8	IDBI Bank	---	---	---	---
9	HDFC Bank	---	---	---	---

पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, केनरा बैंक, एक्सिस बैंक, आई.सी.आई.सी.आई., आई.डी.बी.आई. बैंक एवं एच.डी.एफ.सी. बैंक ने यात्रा मार्ग में 'शाखा खोलने हेतु एस.एल.बी.सी. को अवगत कराया है। वित्तीय सेवाएँ विभाग इस विषय की निगरानी कर रहा है तथा इन बैंकों से 'शाखा खोलने की जानकारी अतिशय चाहता है।

एजेण्डा संख्या – 3 :

कृषि विषयक योजनायं :

(क) कृषि अवसंरचना निधि (Agriculture Infrastructure Fund) :

(Annex. -14)

(Amt. in Cr.)

Target 2020-23	Applications Received		Denied by Central PMU		Rejected by Central PMU		Verified by Central PMU		Sanctioned		Disbursed		Sanctioned %
	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	
314.00	176	105.36	32	36.97	60	23.03	83	45.36	72	41.99	36	20.71	13.37

(Source of Data : Directorate Agr.)

- कृषि अवसंरचना निधि (Agriculture Infrastructure Fund) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-23 हेतु रु. 314.00 करोड़ का बजट निर्धारित है।
- राज्य स्तर पर **Project Management Unit (PMU)** का गठन किया जाना अपेक्षित है।

AIF के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियों को शामिल किया गया है :

- i) व्यक्तिगत, एफ.पी.ओ., पैक्स, एस.एच.जी., जे.एल.जी., एफ.पी.ओ. फेडरेशन, स्टेट लेबल फेडरेशन ऑफ कॉर्पोरेटिब द्वारा कम्युनिटी फार्मिंग एसिस्टस हेतु निम्न गतिविधियां :
 - . फार्म/हारबेस्ट ऑटोमेशन
 - . ड्रॉन्स खरीदने हेतु
 - . रिमोट सेन्सिंग
- ii) एफ.पी.ओ., पैक्स, एस.एच.जी., जे.एल.जी., एफ.पी.ओ. फेडरेशन, एस.एच.जी. फेडरेशन, स्टेट लेबल फेडरेशन ऑफ कॉर्पोरेटिब कम्युनिटी फार्मिंग एसिस्टस हेतु निम्न गतिविधियां :
 - . Hydroponic Farming
 - . Mushroom Farming
 - . Vertical Farming
 - . Aeroponic Farming
 - . Poly house / Green house

विभाग से आग्रह है कि वे उपरोक्त गतिविधियों में AIF अंतर्गत ऋण प्रदान करने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार करें, जिससे कि अधिक से अधिक ऋण उक्त योजना अंतर्गत प्रदत्त की जा सके।

(ख) प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) :

- योजना का लक्ष्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा निजी सूक्ष्म उद्योग की प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाना और क्षेत्र के फार्मलाईजेशन को प्रोत्साहन देना तथा किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और उत्पादक सहकारिताओं (FPOs /SHGs/ Producer Co-operatives) को सहायता प्रदान करना है।
- आवेदक ने यदि किसी अन्य सरकार प्रायोजित ऋण योजना अंतर्गत सब्सीडी प्राप्त की है तथा आवेदक का ऋण खाता स्टेन्डर्ड है, तो वह व्यक्ति PMFME योजना अंतर्गत ऋण हेतु आवेदन कर सकता है।

योजना की विशेषतायें :

- योजना अंतर्गत नई/पुरानी इकाईयों (Individual and Groups) को भी गैर ODOP उत्पाद के लिए ऋण प्रदान किया जाता है।
- योजना अंतर्गत (Individual) सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के लिए परियोजना लागत का 35 प्रतिशत Credit Linked Capital Subsidy अथवा अधिकतम रु. 10 लाख प्रति यूनिट देय है। मार्जिन मनी 10 प्रतिशत है।

PMFME योजना अंतर्गत प्रगति निम्नवत है :

(Annex. – 15)

(रु. करोड में)

प्रगति	लक्ष्य	प्राप्त ऋण आवेदन पत्र	स्वीकृत		वितरित		निरस्त	लम्बित
	संख्या	संख्या	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	संख्या
Upto 31.07.22	578	179	43	4.77	24	2.01	62	74
Upto 31.03.22		90	19	2.36	4	0.21	13	58

(Source of Data : Directorate Agr.)

एजेण्डा संख्या – 4 :

योजनावार एन.पी.ए. :

As on 30th JUNE, 2022

(Amt. in Crores)

S. No.	NAME OF SCHEME	Total Outstanding		Gross NPA		Gross NPA%
		No.	Amount	No.	Amount	
1	PMEGP	6640	175.29	1091	23.13	13.19
2	SCP	4671	41.51	505	3.27	7.87
3	VCSGSY	2564	157.69	596	22.64	14.36
4	NULM	4761	40.69	986	6.92	17
5	NRLM	13698	57.77	1531	6.03	10.44
6	Mudra	416428	3828.52	46628	502.82	13.13

(Source : SLBC Portal)

षासन से निम्नवत आग्रह है :

- सम्बन्धित विभाग को निर्देशित करें कि वे योजना अंतर्गत एन.पी.ए. कम करने में बैंकों का सहयोग प्रदान करें।
- राजस्व विभाग को निर्देशित करें कि राज्य की विभिन्न तहसीलों में बैंकों द्वारा प्रेषित वसूली प्रमाण पत्रों में वसूली हेतु प्रयास करें।

एजेण्डा संख्या – 5 :

(क) एम.एस.एम.ई. :

योजनांतर्गत इकाईयों को वितरित ऋणों की सेक्टरवार outstanding निम्नवत है :

Progress as on 30.06.22

(Total Outstanding Amt. in Cr.)

Micro Enterprises (Manufacturing + Services)		Small Enterprises (Manufacturing + Services)		Medium Enterprises (Manufacturing + Services)		Other Finance to MSMEs		Out of other finance to MSMEs above, loans upto 50 Cr. to Start-ups		Total	
A/c	Amt.	A/c	Amt.	A/c	Amt.	A/c	Amt.	A/c	Amt.	A/c	Amt.
260782	9510.74	24055	7548.90	1945	2536.43	3503	229.74	11	1.53	290285	19825.81

Progress as on 31.03.22

(Total Outstanding Amt. in Cr.)

Micro Enterprises		Small Enterprises		Medium Enterprises		Total Loan Amt.		Total
Manufacturing	Services	Manufacturing	Services	Manufacturing	Services	Manufacturing	Services	
2556.85	4205.11	3835.27	6307.66	1368.40	1014.90	7760.52	11527.67	19288.19

(ख) इमरजेन्सी क्रेडिट लाईन गारंटी योजना :

उक्त योजना रु. 4.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर रु. 5.00 लाख करोड़ कर दिया गया है। योजना रु. 5.00 लाख करोड़ ऋण स्वीकृत होने तक अथवा 31 मार्च, 2023 तक, दोनो में से जो भी पूर्व में हो, तक जारी रहेगी।

जी.ई.सी.एल. योजना अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 30.06.2022 तक **73,407** खाताधारकों को **रु. 2246.60 करोड़** का ऋण स्वीकृत किया गया है।

बैंकों से आग्रह है कि जिन उद्यमियों ने जी.ई.सी.एल. योजना अंतर्गत ऋण नहीं लिया है, उनसे सम्पर्क कर, उन्हे योजना अंतर्गत जानकारी प्रदान करें तथा उनसे प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों को त्वरित स्वीकृत करें।

a) GECL - 1.0 & 2.0 :

Guaranteed Emergency Credit Line (GECL) के अंतर्गत राज्य की योग्य इकाईयों से संबंधित प्रगति निम्नवत है :

Progress as on 30/06/2022, O/S (FB+NFB) upto Rs. 50 Crores :

(Annex. – 16 & 17)

(Rs. In Crores)

		Eligible loan A/Cs		No. of A/Cs whom information sent	No. of Accounts		Amount		Coverage %
		No. of A/Cs	Amt.		Cum. Sanctioned	Cum. Disbursement	Cum. Sanctioned	Cum. Disbursement	
Upto Rs. 25 Crores	Annex. – 16	107683	2562.12	107683	73018	45224	2013.75	1788.32	67.81
Above Rs. 25 to 50 Crores	Annex. – 17	1078	246.63	1078	105	95	164.53	140.90	9.74
Total		108761	2808.75	108761	73123	45319	2178.28	1929.22	---

Progress as on 31/03/2022, O/S (FB+NFB) upto Rs. 50 Crores :

(Rs. In Crores)

		Eligible loan A/Cs		No. of A/Cs whom information sent	No. of Accounts		Amount		Coverage %
		No. of A/Cs	Amt.		Cum. Sanctioned	Cum. Disbursement	Cum. Sanctioned	Cum. Disbursement	
Upto Rs. 25 Crores		107683	2562.12	107683	72966	45152	1957.92	1730.65	67.76
Above Rs. 25 to 50 Crores		1078	246.63	1078	99	89	163.46	139.83	9.18
Total		108761	2808.75	108761	73065	45241	2121.38	1870.48	---

b) GECL – 3.0 :

	Earlier	Now
Entities / Sector eligible	Hospitality, Travel & Tourism, Leisure & Sporting sectors	Civil aviation sector also made eligible
Scheme validity	June 30 th , 2021	31 st March, 2023
Ceiling	Rs. 500 crore of loan outstanding	No limit (assistance to each borrower limited to 40% of total credit outstanding or Rs. 200 crore whichever is lower)

(Annex. – 18)
(Amt. in Cr.)

Progress

	No. of Accounts	Amount
Upto 30/06/2022	274	65.75
Upto 31/03/2022	259	62.86

ईमरजेन्सी क्रेडिट लाईन गारंटी योजना अंतर्गत रु. 4.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर रु. 5.00 लाख करोड़ कर दिया गया है, जिसमें से रु. 50,000 करोड़ पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र को ऋण देने के लिए रखे गये हैं।

c) GECL – 4.0 :

(Annex. – 18)

Progress

(Amt. in Cr.)

	No. of Accounts	Amount
Upto 30/06/2022	10	2.57
Upto 31/03/2022	10	2.57

एजेण्डा संख्या – 6 :

लम्बित प्रकरण :

(i) Issues pending with State Government :

क्र.सं	विषय	वर्तमान स्थिति
1.	कृषि ऋण पर स्टाम्प शुल्क में छूट	षासन की अधिसूचना संख्या 160/2016/XXVII(9)/स्टाम्प-55/2009, दिनांक 30 जून, 2016 में आंशिक संशोधन करते हुए आगामी 05 वष अर्थात् दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2022 तक रु. 5,00,000.00 (रु. पांच लाख मात्र) तक के कृषि सम्बन्धी क्रिया-कलापों के प्रयोजनार्थ लिये गये ऋणों हेतु निष्पादित बन्धक विलेखों पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य न किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। शासन से उक्त विषयक सूचना अपेक्षित है।
2.	स्वामित्व योजना	निम्न कार्य विन्दुओं पर शासन स्तर पर कार्यवाही प्रतीक्षित है। a. Legal recognition of SVAMITVA card under State Land Revenue Act. b. Provision to be made for registration of SVAMITVA cards on the lines of State Act/Rule of Haryana Government, making. c. Modalities for creation of mortgage / noting of charge on SVAMITVA card treating these as Title of Property.
3.	कर्णप्रयाग शाखा	भारतीय स्टेट बैंक को कर्णप्रयाग में शाखा खोलने हेतु ए.टी.एम. के लिए उपलब्ध करायी गयी भूमि के साथ शाखा खोलने हेतु स्थान उपलब्ध कराना।

(ii) Issues of SLBC pending with Banks :

क्र.सं	विषय	वर्तमान स्थिति
1.	दिनांक 04.01.2021 को एस.एल.बी.सी. की 80वीं बैठक में माननीय राज्य वित्त मंत्री, भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार विभिन्न बैंकों द्वारा 58 नई शाखाएँ खोली जानी थी।	भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 02 शाखाएँ, बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा 02 शाखाएँ, केनरा बैंक द्वारा 03 एवं पंजाब नेशनल बैंक द्वारा 01 शाखा खोले जाने की सूचना प्राप्त हुयी है। बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, यूको बैंक, इण्डियन ओवरसीज बैंक, एच.डी.एफ.सी. बैंक से नई शाखा खोलने की सूचना प्रतीक्षित है।
2.	राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के Circular Instruction एवं Product Code जारी करना	वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना, पं. दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना – नैनो, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना विषयक सर्कुलर भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, सेन्ट्रल बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया, आई.डी.बी.आई., उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी बैंक, नैनीताल बैंक द्वारा जारी किये गये हैं। पंजाब नेशनल बैंक एवं पंजाब एण्ड सिंध बैंक द्वारा एक मात्र योजना मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का सर्कुलर जारी किया गया है। अवशेष बैंकों से अपेक्षा है कि वे उपरोक्त योजना से सम्बन्धित सर्कुलर अतिशीघ्र जारी करेंगे, ताकि उक्त योजनाओं अंतर्गत प्रगति दर्ज हो सके।
3.	पी.एम. स्वनिधि योजना	पी.एम. स्वनिधि योजना अंतर्गत 2 nd tranch & 3 rd tranch में rejection का option नहीं है, अतः इस विषयक बैंकों से सूचना प्रतीक्षित है।
4.	स्वामित्व योजना	बैंकों से उनके विधि विभाग से स्वामित्व योजना पर टिप्पणी प्रतीक्षित है।
5.	Market Intelligence	Ponzi Schemes / Illegal Activities of Unincorporated Bodies / Firms / Companies Soliciting Deposits from the Public : उक्त विषयक यदि किसी भी बैंक के कार्य क्षेत्र में इस प्रकार की घटना घटित हुई है, तो वे वर्णित घटना से एस.एल.बी.सी. को अवगत नहीं कराया गया है।
6.	बी.सी. को सी.एस.सी. के कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाना	बैंकों द्वारा बी.सी. को सी.एस.सी. के कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाने की सूचना प्रतीक्षित है।

एजेण्डा संख्या – 7 : अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा।

.....